>

Title: Regarding National Rural Employment Guarantee Scheme.

श्री मानिक सिंह (सीधी) : महोदय, राÂष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के माध्यम से निश्चित ही यूपीए सरकार की मंशा रही कि देश के पूत्येक मजदूर, किसान तबके के लोग, जो मजदूरी पर आश्रित रहते हैं, उन्हें दो वक्त की रोटी मिले तथा उनके घर में भी चूल्हा जले। मध्य पूदेश में, खास कर आदिवासी क्षेतू की बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं वहां से मैं आता हूं, सतना जिले की बात है। वहां कुपोषण से 28 बच्चों की मृत्यु हो गई। छह-छह मास से उनकी मजदूरी लम्बित है। पीएस से लेकर मूल्यांकन तक के लिए सरपंचों को 35 परसेंट से 40 परसेंट तक खर्च करना पड़ता है। मेरा मंतूी जी से निवेदन है कि निश्चित ही आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिस मकसद हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मकसद के लिए यह योजना तभी कारगर सिद्ध होगी, जब उसकी मोनिटरिंग के लिए कोई कमेटी बनाएंगे।